

ई-कॉमर्स पॉलिसी में उपभोक्ता केशिकायत निपटान के लिए खास इंतजाम, ऑफलाइन कारोबारियों को भी मिलेगा अवसर

नई दिल्ली। कई सालों से लंबित ई-कॉमर्स पॉलिसी जल्द लाई जा सकती है। हाल ही में इस मामले में ई-कॉमर्स कंपनियां और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ उद्योग विभाग में बैठक की गई थी। अब ई-कामर्स पॉलिसी का अंतिम दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ई-कामर्स पॉलिसी में उपभोक्ता के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनकी शिकायतों के निपटान के लिए ठोस मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। अभी कई बार ई-कॉमर्स के जरिए सामान मंगाने पर उपभोक्ता ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार, इसकी शिकायत उपभोक्ता मामले विभाग के पास की जा सकती है, लेकिन कई बार इसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। इसलिए ई-कॉमर्स शिकायत के लिए अलग से सेल की स्थापना हो सकती है और एक तय समय में उसका निपटान किया जाएगा। पॉलिसी में ऑफलाइन काम करने वाले छोटे कारोबारियों को कारोबार का समान अवसर दिताने का भी ध्यान रखा जाएगा। अभी ई-कॉमर्स कंपनियां त्योहारी सीजन के लेकर सभी विशेष अवसरों पर सामान की बिक्री पर भारी छूट देने की घोषणा कर देती हैं। इससे ऑफलाइन कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी प्रभावित होते हैं। सूत्रों के मुताबिक, पॉलिसी में लागत से कम मूल्य पर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर किसी प्रकार की वस्तु की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। पॉलिसी में सभी प्रकार के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं का ई-केवाईसी अनिवार्य हो सकता है।

विश्वकर्मा योजना को अंतिम रूप देने में जुटी सरकार, 28 अगस्त को सभी राज्य और बैंक प्रमुखों की बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए 28 अगस्त को सभी राज्य सरकार के साथ बैंक के शीर्ष अधिकारी बैठक करेंगे, ताकि सितंबर में शुरू होने वाली इस योजना के अमल में कोई दिक्कत नहीं हो। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के आगामी सात महीनों में विश्वकर्मा योजना के तहत तीन लाख पारंपरिक पेशेवरों को एक-एक लाख लोन दिया जाएगा। सरकारी सिव्डीके के तहत इस लोन पर सिर्फ पांच प्रतिशत का ब्याज होगा।। सरकार की तरफ से इस लोन की गारंटी भी ली जाएगी। एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास विभाग और डीएफएस मिलकर इस योजना को अमल में लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इस स्कीम की घोषणा की थी जिसकी मंजूरी कैबिनेट से भी मिल चुकी है। ग्रामीण व शहरी स्तर पर चुने गए पात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी और दूल् कित खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई-वाउचर दिया जाएगा। मतलब वे इस पैसे का इस्तेमाल करहीं और नहीं कर पाएंगे। सेविंग खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखे जाने पर अब भी कई बैंक खाताधारकों से जुर्माना वसूल रहे हैं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में आरबीआई से बातचीत की जाएगी। पिछले पांच सालों में न्यूनतम बैलेंस कम होने पर बैंकों ने खाताधारकों से 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। डीएफएस सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई की इजाजत से बैंक खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं होने पर कुछ शुल्क लेते हैं। हालांकि, एसबीआई जैसे बैंक ने इस प्रकार के शुल्क को लेना बंद कर दिया है। डीएफएस के मुताबिक, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) एकाउंट के तहत न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है और देश भर में इस प्रकार के 70 करोड़ खाते हैं।

50 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, राष्ट्रपति मुर्मू पांच सितंबर को करेंगी सम्मानित



नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पांच सितंबर को दिल्ली में देशभर के 50 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन स्तरों पर मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया है। मंत्रालय ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 की सूची राज्यों और प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग को भेजी गई। इन शिक्षकों को अवार्ड के रूप में प्रमाणपत्र और 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। सभी शिक्षक तीन सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अस्ती नगर की आसिया फारूखी, बुलंदशहर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज के चंद्र प्रकाश अग्रवाल, मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल के सुधांशु शेखर पांडा, हरियाणा से रेवाड़ी जिले के बुरोली सरकारी स्कूल के सत्यपाल सिंह, हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा जिले के सरकारी स्कूल इंदौरा के विजय कुमार, पंजाब के लुधियाना के अमृतपाल सिंह, सेंट पॉल मिशनल स्कूल के भूपिंदर गोिया, दिल्ली के एसकेवी लक्ष्मी नगर की आरती कानुंगो, पश्चिम विहार के सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल की रितिका आनंद, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के दैलत सिंह गोसाईं, चंडीगढ़ के सेक्टर 14 गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के संजय कुमार, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के रंयाज अहमद शेख समेत 50 शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है।

हरियाणा में हर 20 किमी पर कॉलेज की घोषणा बनी जुमला : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़, एजेंसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा है हर 20 किमी पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की प्रदेश सरकार की घोषणा भी जुमला बनकर रह गई है। कालेजों में पहले से ही प्राध्यापकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

सरकार को सबसे पहले खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य वहां की युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। उच्च शिक्षा के लिए आज भी प्रदेश के युवाओं की दूसरे राज्यों की ओर गमन करना पड़ रहा है।

मोडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश में करीब 180 सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें प्राध्यापकों के करीब 8000 पद हैं। इनमें से 3600 पद ही भरें हुए हैं यानी 4400 पद खाली हैं। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में एंडेड कॉलेजों की संख्या 97 है और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 94 है। सरकारी कॉलेज में करीब 21 लाख से अधिक विद्यार्थी, एंडेड कॉलेजों में करीब 14 लाख और प्राइवेट कॉलेज में करीब 32 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं।

राहुल गांधी हैं कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार-अशोक गहलोत

मुंबई, एजेंसी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है। गहलोत ने इंडिया टुडे रूप के साथ बात करते हुए दावा किया है कि यह फैसला सभी दलों ने चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया है। इंडिया गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, जनता ने ऐसा दबाव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है।

गहलोत ने आगे कहा, पीएम मोदी को अहकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31 प्रतिशत वोटों के साथ सत्ता में आई थी। बाकी 69प्रतिशत वोट उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब पिछले महीने बंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है।

अशोक गहलोत से जब बीजेपी के उन दावों के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50व वोटों के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रहा है तो उन्होंने कहा, पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तो वह ऐसा कर सकते थे। उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।

अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी की बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि

रोमानिया में गैस स्टेशन पर विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल

चिसिनूआ, एजेंसी

रोमानिया के बुखारेस्ट उपनगर में शनिवार रात एक गैस स्टेशन पर हुए चार विस्फोटों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आंतरिक मामलों के मंत्रालय में आपातकालीन स्थिति विभाग के प्रमुख राएद अराफात ने संवाददाताओं से कहा, ह्यश्रुकूआत में छह नागरिक घायल हो गए... दुर्भाग्य से, दूसरे विस्फोट में 26 अग्निशामक घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य झुलस गए। श्री अराफात ने कहा कि गैस टैंक के पहले विस्फोट से आग लग गई जो दूसरे टैंक तक फैल गई और एक नया विस्फोट हुआ। गैस स्टेशन के आसपास 300 मीटर क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और वहां रहने वाले लोगों को हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाद में कहा कि पहले विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात घायल हो गए। इसके बाद तीन और विस्फोट हुए, जिससे

घायलों की संख्या 46 हो गई। कम से कम 16 मरीजों को कुत्रिम वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी। हाताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल सिओलाकू ने एक समाचार ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने अन्य सदस्य देशों से चिकित्सा सहायता का अनुरोध करने के लिए यूरोपीय संघ नागरिक सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने कहा कि विस्फोट में घायल चार लोगों को इवाई मार्ग से बेल्जियम और इटली के अस्पतालों में ले जाया जाएगा।

जा रहा है जिनकी नौकरी पर उन्हें हटाए जाने की तलवार हर समय लटकती रहती है। इनको स्थायी नियुक्तियां प्रदान की जा सकती है।

सरकार ऐसा करने से भी बच रही है। जब भी चुनाव को समय आता है युवाओं के लिए बंपर नौकरी देने की घोषणाएं की जाती हैं बाद में चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर आगे कदम नहीं बढ़ाया जाता। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का शीर्षक होता है। आने वाले चुनाव में युवा इस सरकार को सबक सिखाकर रहेंगा।

राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन की चेतावनी पर बोले पंजाब सीएम, चर्चनयंत्रण में है कानून व्यवस्था
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा उनके सवालों का जवाब न देने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की चेतावनी देने एक दिन बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि वह पहले ही 16 में से 9 सवालों का जवाब दे चुके हैं। मान ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दों, ड्रप्स और कानून व्यवस्था पर पर्याप्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने

50 करोड़ लोगों को बिजली दे सकता है सीवर का पानी, कारगर नीतियों की जरूरत पर जोर



नई दिल्ली, एजेंसी।

नालियों और सीवरों के जिस अपशिष्ट पानी को पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या समझा जाता है वह उपयोगी भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई रिपोर्ट वेस्टवाटर-टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन के अनुसार कारगर नीतियों का मदद से इस दूषित जल की समस्या का न सिर्फ समाधान हो सकता है, बल्कि इससे 50 करोड़ लोगों के लिए वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था और चार करोड़ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी की जा सकती है। इस सिंचित जमीन का आकार करीब जर्मनी के बराबर जितने खेतों की सिंचाई करने जितना है।

इतना ही नहीं इस अपशिष्ट जल में मौजूद पोषक तत्व खेतों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। अनुमान है कि यदि इसमें मौजूद पोषक तत्वों के दोबारा उपयोग

से सिंथेटिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता को काफी कम किया जा सकता है। इसकी सहायता से खेती-बाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग को 25 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रति वर्ष लगभग 32 हजार करोड़ क्यूबिक मीटर अपशिष्ट पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 50 फीसदी दूषित पानी को बगैर स्वच्छ किए नदियों, झीलों और समुद्र में छोड़ा जा रहा है।

अध्ययन के अनुसार, इस प्रक्रिया से पानी की भारी बर्बादी रोकने में सफल हो सकते हैं। इस समय भारत सहित दुनिया की एक बड़ी आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआई) के आंकड़ों के इसमें मौजूद पोषक तत्वों के दोबारा उपयोग

में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। ये वे देश हैं जो अपनी जल आपूर्ति का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। यह समस्या केवल इन्हीं देशों तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की करीब 50 फीसदी आबादी यानी 400 करोड़ लोग साल में कम से कम एक महीने पानी की भारी किल्लत का सामना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में घरेलू और शहरी स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा 38 हजार करोड़ क्यूबिक मीटर थी, वह 2030 तक बढ़कर 49,700 करोड़ क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में इस अमूल्य संसाधन को ऐसे ही नाली में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में मात्र 11 फीसदी ट्रीटेड वाटर का पुनः उपयोग किया जाता है। फ्रांस में मात्र 0.1 फीसदी अपशिष्ट जल को साफ करने के बाद फिर से उपयोग किया जाता है।

सीरिया में विद्रोहियों के हमले में ग्यारह सैनिकों की मौत

दमिश्क, एजेंसी

सीरिया के उत्तर-पश्चिमी प्रांत इदल्लिब में शनिवार को विद्रोहियों के हमले में ग्यारह सैनिकों की मौत हो गयी और 20 अन्य घायल हो गए। मानवाधिकारों के लिए सीरिया वेधशाला (एसओएफआर) ने कहा कि हमलावरों ने हमला किया और इदल्लिब के दक्षिणी ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सेना की चौकियों के नीचे सुरगों में छिपाए गए विस्फोटक उपकरणों में विस्फोट कर दिया। वेधशाला ने कहा कि हमलावर अंसार अल-तौहीद गुट और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सहित गुटों से हैं, दोनों हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) विद्रोही गुट के सहयोगी हैं। एचटीएस और सीरियाई सेना के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों पक्षों के बीच उत्तरी सीरिया में गोलीबारी हो रही है। वेधशाला के अनुसार, एक दिन पहले, उत्तरी सीरिया में अलेपो के पश्चिमी ग्रामीण इलाके में सैन्य बलों ने सात एचटीएस सदस्यों को मार गिराया था। सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार, सोमवार को सीरियाई बलों ने इदल्लिब और हमा के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में एचटीएस द्वारा भेजे गए तीन हथियारबंद ड्रोनों को रोका और मार गिराया।

कार्यालय नगर पंचायत नौगावां सादात, जनपद अमरोहा

पत्रांक: 25 /न0पा0नौ0सा0 / 2022–23

दिनांक:27–08–2023

ई–निविदा सूचना

शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य 15 में वित्त आयोग की टाईड/ अनटाइड ग्राण्ड से प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जा रही है।
अतः इच्छुक निविदादाता / ठेकेदार/ फर्म अपनी-अपनी ऑनलाईन निविदाये दिनांक 11.09.2023 दोपहर 12.00 तक <https://etender-up-nic.in>. पर आनलाईन प्रस्तुत कर सकता है जो कि दिनाक 11.09.2023 को ही अपराह्न 12.00 बजे गठित समिति तथा पंजीकृत ठेकेदारी/ निविदादाता/फर्मों की उपस्थिति में खोली जायगी।
ई–निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।जोकि बेवसाईट <https://etender-up-nic.in> पर उपलब्ध है। निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार अध्यक्ष महादय/अधिसारी अधिकारी नगर पंचायत नौगावा सादात में निहित है।इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर किसी भी ठेकेदारों/ निविदादाता / फर्मों को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।

E-bid reference No.	25/N.P.N.S.-Tender/2023-24
Publish date and time.	28.08.2023 on 12:00 PM
Last date and time for submission of E-bids	11.09.2023 on 12:00 PM
Date and time of opening of on line TE-Bids	11.09.2023 on 12:00 PM
Place of opening of E-Bids	E.O office Nagar panchyey Nowgawan Sadat Amroha
E- Tender Security	10% of tender Value
E- Tender document processing	AS per tender list
अधिशारी अधिकारी	नौगावा
नगर पंचायत नौगावां सादात	नगर पंचायत नौगावां सादात
जनपद अमरोहा	जनपद अमरोहा

मुद्रक तथा प्रकाशक रंजीत राय द्वारा स्वामी आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-16 एवं 17, रोड नं. 9, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रीएल एरिया, पटना-800013 के पक्ष में आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेस से मुद्रित एवं सी-20, पक्ष.के. पुरी, निगर बसावत पार्क, पटना, बिहार-800013 से प्रकाशित संपादक- देवबन प्रसाद

(नोट- प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं और किसी भी कानूनी बाद-पिनाद का निपाटारा पटना न्यायालय में ही किया जाएगा।)
RNI.No. BIH13N/2013/49676, Email: news@pratahkiran.com, patna@pratahkiran.com, 9212228045, 8130691216, 9971557129